

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 653)

20 ज्येष्ठ 1937 (श0) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-05/2007/872—श्री चिन्द्रका प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, राघोपुर के विरूद्ध वर्ष 2006 में एजेण्डा सं0-84/100 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्य स-समय पूरा नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 285 दिनांक 29.03.2007 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0- 430 दिनांक 10.03.2010 द्वारा उन्हें निम्न दंड संसूचित किया गया -

1. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

उक्त संसूचित दंड के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री राय दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत हो जायेंगे। अतएव उनके विरूद्ध संसूचित दंड प्रभावी नहीं होता है।

तत्पश्चात मामले की समीक्षा की गयी एवं श्री राय से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत मात्र कारण पृच्छा पूछकर छः प्रतिशत पेंशन पर दो वर्ष तक के लिए रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया परन्तु उक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस आधार पर सहमति नहीं दी गयी कि सेवानिवृत के उपरांत वृहद दंड अधिरोपित करने के लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन आवश्यक है।

तदुपरान्त मामला कालबाधित हो जाने के कारण श्री राय के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं० ४३० दिनांक 10. 03.2010 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त मुख्य सचिव के माध्यम

से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्ति के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा पृच्छा की गयी कि — "क्या पेंशन नियमावली के नियम—139 में कार्रवाई संभव नहीं है।"

मुख्य सचिव की पृच्छा के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम—139 के तहत कार्रवाई पर विचार के क्रम में पाया गया कि श्री राय के पक्ष में पूर्ण पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 1101 दिनांक 12.07. 2010 द्वारा दी गयी है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम—139 (ग) के तहत किसी सेवानिवृत सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्रवाई उसके प्रथम पेंशन की स्वीकृति की तिथि से तीन साल के भीतर ही की जा सकती है। अतः श्री राय के प्रथम पेंशन की स्वीकृति तीन वर्षों से अधिक हो जाने के कारण इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई संभव नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर समीक्षोपरान्त श्री चिन्द्रका प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0—'430 दिनांक 10.3.10 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

तदालोक में श्री चिन्द्रका प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, राघोपुर सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय अधिसूचना सं0—'430 दिनांक 10.3.10 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 653-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in